FIRST SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT (EXCLUDING RAILWAYS) FOR THE YEAR 1977-78

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL): Sir, with your permission, on behalf of the Finance Minister, I beg to lay on the Table a statement (in English and Hindi) showing the First Supplementary Demands (December 1977) for Grants *for Expenditure of the Central Government* (excluding Railways) for the year 1977-78.

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1974—Contd.

(To amend Article 312)

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, इस विधेयक के पीछे जो भावना है, मैं उसका समर्थन करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, जहां चुने हुए लोग शासन करते हैं और उनके हाथ में शासन-सूत्र रहता है, वहां इस बात की सम्भावना ज्यादा रहती है, कि ऐसे लोग मंत्री बने, जिन्हें बहुत विस्तृत और विस्तार की जानकारी न हो।

[The Vice-Chairman (Shri U. K. Lakshmana Gowda) in the Chair]

यहां इस बात की भी सम्भावना रहती है कि उन्हें बहुत अनुभव भी न हो। नये व्यक्ति चुनकर आते हैं और मंत्री हो जाते हैं और उनको शासन-सूत्र सम्भालना पड़ता है। उनकी सहायता के लिये, उनको राय देने के लिये, उनके नीचे जो नौकरशाही होती है, उसको मंत्री की ईमानदारी से सहायता करनी चाहिए, उनकी जानकारी में सारी चीजें लानी चाहिए, ताकि वह जन-हित में अपना निर्णय ले सके।

श्रीमन्, मैं उदाहरण दे कर बताऊंगा कि यह आई०ए०एस० का काडर जो पहले आई० सी० एस० काडर हुआ करता था, कितना मजबूत होता है। और अपने तौर तरीकों में कितनी मनमानी करता है। मुझे याद है कि जिस समय द्वितीय महायुद्ध चल रहा था उस समय अमरीका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और अमरीका की जनता इस बात का प्रयास कर रही थी कि अंग्रेजी सरकार इंडियन नेशनल कांग्रेस का सहयोग प्राप्त कर, गांधी जी की शर्तों को मान ले और किसी तरह हिन्दुस्तान की जनता का सहयोग अलाइस की फेवर में प्राप्त किया जाए। इसके लिए वे चाहते थे कि चर्चिल गांधी जी के साथ किसी प्रकार का सुलहनामा करें लेकिन चर्चिल यह कहा करते थे कि हिन्दुस्तान की समूची जनता हमारे साथ है, कांग्रेस के थोड़े से नेता जो प्रभावहीन हैं वही सिर्फ खिलाफत में थे। इस संदर्भ में हिन्दुस्तान से दो विशिष्ट महिलाएं हिन्दुस्तान से अमरीका गई थी श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित और श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय। उन्होंने अमरीकी जनता को भारतीय परिस्थितियों से और यहां की जन-भावना से अवगत कराने का प्रयास किया। इसके उपरांत चर्चिल साहब ने वायसराय को हिदायत दी कि यहां किसी को भेजा जाए ताकि इन भारतीय महिलाओं के विचारों को और प्रचार को कंट्रेडिक्ट किया जा सके। हिन्दुस्तान से वायसराय ने उस समय एक ऊंचे अफसर गिरिजाशंकर वाजपेयी को अमरीका भेजा और गिरिजाशंकर वाजपेयी ने वहां पब्लिक मीटिंग्स में हमारी इन आदरणीय महिलाओं के संबंध में गंदे शब्दों को इस्तेमाल किया जिसका वर्णन नही किया जा सकता है। उन्होंने श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित को भ्रष्ट महिला तक कह डाला। उनकी बात हिन्दुस्तान के अखबारो में छपी और यहां सभी लोगो में इससे बहुत गुस्सा पैदा हुआ। पंडित जी जब यहां पर प्रधान मंत्री हुए तो उन्होंने पहला काम यह किया कि गिरिजाशंकर वाजपेयी को सैक्रेटरी जनरल बना दिया। इस पर जनता में काफी रोष हुआ कि गिरिजाशंकर वाजपेयी

[श्री नागेश्वर प्रसाद शाही]

जैसे अफसर को पंडित जी ने सैक्रेटरी जनरल क्यों बना दिया । मुझे याद है लखनऊ में पी० सी० सी० की मीटिंग के अन्दर जब कि टंडन जी अध्यक्ष थे, पंडित जी थोड़ी देर के लिए वहां गए दूसरे तो किसी की हिम्मत नहीं हुई लेकिन टंडन जी ने जरा सा जिक्र किया कि पंडित जी इस से बड़ा जनरोष है । इस बात पर पंडित जी बिगड़ गए और गुस्से में उन्होंने कहा कि

I cannot control these British I.C.S. Officers. It is Girija Shankar alone who can control them. Therefore I have appointed him Secretary-General.

श्रीमन् यह दशा थी । पंडित जी जैसी टावरिंग परसनलटी जो दूसरों पर हैड एंड शे शोल्डर की तरह थे, वे यह महसूस करते थे कि आई० सी० एस० अफसरों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते ।

श्रीमन्, मैं एक दूसरा उदाहरण दे रहा हूं । इस इमरजेंसी के दौरान विश्व की सबसे जोरदार महिला श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ इन आई० सी० एस० आफिसरों ने क्या व्यवहार किया, जब इमरजेंसी लागू हो गयी और पहली बार यहां संसद की बैठक हुई उस इमरजेंसी के दौरान, कांग्रेस पार्टी के मेम्बरों की बैठक हुई, तब उसमें जाहिर था कि संसद सदस्य काफी उद्विग्न थे, उद्वेलित थे कि कैसा इंतजाम चल रहा है, इस इमरजेंसी का बहाना लेकर अधिकारी कितने जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं । श्रीमती गांधी ने सदस्यों को आश्वासन दिया कि मैं यह स्कीम बना रही हूं कि :

MPs and elected representatives will be involved in the implementation of the 20-point programme.

और वहीं उन्होंने घोषित किया कि वी० बी० राजू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी जायगी । उस कमेटी को यह रिपोर्ट देनी थी कि कहां :

MPs and elected representatives will be involved in the implementation of the 20-point programme.

उस कमेटी की जो पहली बैठक हुई उसमें आई० ए० एस० आफिसरों ने एतराज पेश किया

How can these people be involved in the implementation of the 20-point programme? These MPs and MLAs cannot be involved.

और उनका एतराज इतना जोरदार था कि वी० वी० राजू की कमेटी की रिपोर्ट आज नहीं आयी । दूसरी मीटिंग भी नहीं हुई और आज तक कोई रिपोर्ट नही आयी । श्रीमन्, इंदिरा गांधी जैसी शक्तिशाली और पावरफुल प्रधान मंत्री के साथ यह सलूक आई० ए० एस० आफिसरों का था । उनकी भी हिम्मत नहीं हुई उनके मामलों में दखल देने की . . . .

(*Interruptions*)

श्री नृपति रंजन चौधरी (आसाम) : क्या आप यह कहना चाहते है कि मोरारजी देसाई भी यह नहीं कर सकेंगे ।

DR. RAJAT KUMAR CHAKRABARTI: How do you know, Mr. Choudhury? That is why I have brought forward this Bill. Now the Government must do it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Mr. Choudhury, you can say all these things when you speak.

SHRI NAGESHWAR PRASAD SHAHI: He is saying it only for this purpose that Morarjibhai may be aware of it and beware of it.

SHRI N. G. RANGA (Andhra Pradesh): If that is so, it is all right.

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : तो मैने श्रीमन् यह दो उदाहरण दिये । एक तीसरा अच्छा उदाहरण और दे दूं कि श्री सजय गांधी जी जिस तरह से अधिकारियों के साथ और अधिकारियों के मामलों में दखल

देते थे, वह सब तो जाहिर है । यह मामला यहां दिल्ली में हुआ था । उन्होंने किसी ज्वाइंट सेक्रेटरी को इशारा किया कि वह अपनी रिपोर्ट बदल दें किसी मामले पर, परन्तु उस ज्वाइंट सेक्रेटरी ने अपनी रिपोर्ट बदलने से इंकार कर दिया । दूसरे दिन उस ज्वाइंट सेक्रेटरी के यहां सी० बी० आई० ने सर्च किया, उस ज्वाइंट सेक्रेटरी ने इस्तीफा दे दिया प्रोटेस्ट में । इसके दूसरे दिन ही सारे आई० ए० एस० आफिसरों की मीटिंग हुई और उन्होंने रिप्रेजेंट किया श्रीमती गांधी को कि हम लोगों के साथ यह सलूक होगा तो हम लोग काम नहीं करेंगे, इस्तीफा दे देंगे । श्रीमती गांधी ने कैबिनेट सेक्रेटरी के माध्यम से यह एश्योरेंस दिया कि इस तरह की बात आइन्दा नहीं होगी और तब कैबिनेट सेक्रेटरी ने एश्योर करके उस ज्वाइंट सेक्रेटरी का इस्तीफा वापस कराया । तो दूसरों के साथ तो चल गयी लेकिन आई० ए० एस० आफिसरों के मामले में श्री संजय गांधी भी फेल हो गये । इनका रेजिस्टेंस इतना तगड़ा है, इनका संगठन इतना मजबूत है कि ...

(Interruptions)

डा० चन्द्रमणि लाल चौधरी (बिहार) : क्या आप मानते हैं कि इंदिरा गांधी बहुत शक्तिशाली थीं ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Mr. Shahi, you continue with your speech. If you go on giving examples, your time will be over. Already your time is up.

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : श्रीमन, मैंने उस समय भी कहा था और श्रीमती इंदिरा गांधी को भी कन्वे किया था कि इन आई० ए० एस० आफिसरों ने 20 प्वाइंट प्रोग्राम का, जो बहुत अच्छा प्रोग्राम था, किस तरह से मखौल उड़ाया । इस बात को हमने श्रीमती इंदिरा गांधी को भी बता दिया था ।

एक आफिसर्स क्लब में रात को जब आइ०ए०एस० आफिसर्स बैठे तो एक आफिसर ने कहा भई, मुझे तो काम से छट्टी मिलती नहीं, सारी फाइलें पड़ी हुई हैं डिस्पोज आफ करने के लिए । दूसरे आफिसर ने कहा तुम बेवकूफ हो जो फाइलें डिस्पोज आफ करते हो, टुन्टी टुपौइंट प्रोग्राम क्यों नहीं करते हो । उनका आपस की बातचीत में ट्वेन्टी पौइंट प्रोग्राम एक जोक का शब्द था; आपस में जब ये लोग जोक करते थे, मजाक करते थे तो ट्वेन्टी पोइंट प्रोग्राम का जिक्र करते थे । यह परफारमेंस, यह रवैया और यह रुख--यही कारण है कि जो अच्छे प्रोग्राम भी हुए वे भी आज तक फुलफिल नहीं हुए, और ये आइ० ए० एस० आफिसर्स जानते हैं कि ये सरकार के ऊपर बैठे हुए मंत्रियों को कैसे मूर्ख बनाया जाए, कैसे उन्हें बेवकूफ बनाया जाए । अगर सरकार कहती है कि ये कोटा तुम्हें पूरा करना है, इतने लाख एकड़ जमीन हरिजनों में बाटनी है, वे फिगर्स जाते हैं जिला कलक्टर के पास कि यह तुम्हारा कोटा है, 10,000 हरिजनों को जमीन बांटना है । तहसीलदार को कोटा बट जाता है, तहसीलदार आ जाता है । कहता है, साहब जमीन तो है नहीं, बांटें कैसे ? "अजी, कैसा बेवकूफ आदमी है, लिख कर भेज दो कि 13 लाख 24 हजार हेक्टर जमीन बाट दी गई ।" तो इस तरह की हर तहसील से हर जिले से रिपोर्ट आ जाती है और दिल्ली में फिगर कंपाइल हो जाते हैं कि 13 लाख 24 हजार हेक्टर जमीन हरिजनों में बांट दी गई और ये फिगर्स--मंत्री जी उठते है और संसद में सुना देते हैं । अगर ये सारे फिगर्स जोड़ लिए जाएं, जितनी जमीन आज तक बांटी गई, तो उतनी जमीन हिन्दुस्तान में नहीं है ।

DR. RAJAT KUMAR CHAKRABARTI: It is just like giving comparative figures during a war about the dead. The number of the dead that

[Dr. Rajat Kumar Chakrabarti]

is given is more than the total number of human beings.

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : तो श्रीमन्, मै यह कह रहा था कि अगर डिपार्टमेंटल हेड्स और सेक्रेटरीज, अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के, उस डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट्स है तो निश्चित है आइ०ए०एस० आफिसर जब सेक्रेटरी होगा तो उसकी एडवाइस मे और एक जो डाक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट होगा सेक्रेटरी, तो दोनों की एडवाइस में नजरिए मे, फर्क होगा, दोनों में अपने रुख का फर्क होगा । दोनों की एडवाइस में, दोनों के रवैये में बहुत फर्क होगा । और उसी प्रकार जब एक स्पेशलिस्ट राय देगा मिनिस्टर को, तो उसका मिनिस्टर से संबंध, उसका मिनिस्टर के प्रति अपना बिहेवियर, अपना सलूक, अपना नजरिया बिलकुल भिन्न होगा एक आइ०ए०एस० आफिसर के नजरिए से ।

(Time bell rings.)

मैं खत्म कर रहा हूं, श्रीमन् ।

दूसरी बात यह है श्रीमन्, कि साइंटिस्टस और स्पेशलिस्ट्स लोग आइ०ए०एस० आफिसर्स के अंडर काम करने में अपने को डिप्रेस फील करते हैं । बहुत बड़ा कोई वैज्ञानिक होगा तब भी उसके काम के संबंध में आखरी फैसला आइ०ए०एस० आफिसर को करना होगा । कोई रिसर्च वर्क कंडक्ट किया जाए, न कंडक्ट किया जाए, किस रिसर्च मे कितने इम्प्लीमेंट्स या वैज्ञानिक सामग्री की आवश्यकता है, कितना इम्पोर्ट किया जाए, कितना खरीदा जाए इसका फैसला वैज्ञानिक के हाथ नही रहता । इसका फैसला, आखरी फैसला, आइ०ए०एस० आफिसर करता है जिसको कोई जानकारी उसके संबंध मे नहीं है । किसी स्वास्थ्य संबंधी अन्वेषण के संबंध मे कहां क्या काम किया जाए, किसी डाक्टर को कहां कौन काम दिया जाए, किसी मैडिकल कालेज में क्या व्यवस्था की जाए, इसका सारा फैसला आइ०ए०एस० आफिसर करता है । नतीजा यह होता है कि वैज्ञानिक और स्पेशलिस्ट्स यह महसूस करते है कि उन्होंने जो कुछ अपनी बुद्धि से तय किया उसका कोई महत्व नही है और उनकी रिपोर्ट जब आई०ए०एस० अफसर के पास जायेगी और उस पर वह जो निर्णय लेगा वही फाइनल होगा । इसलिये उसको अपने ऊपर भरोसा नही रहता । जो काफिडेंस चाहिए सारी चीजों के लिये अपनी सक्सेस के लिये उसे वह प्राप्त नहीं कर पाता है इन० आई० ए०एस० अफसरों के डामिनेशन की वजह से । एक आई० ए० एस० अफसर सेक्रेटरी भी हो सकता है या किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी हो सकता है और किसी फैक्टरी का मैनेजर भी हो सकता है । उत्तर प्रदेश मे कई यूनिवर्सिटीज मे उन को वाइस चांसलर बना दिया गया है । किसी फैक्टरी का वह जनरल मैनेजर भी हो सकता है । हमारी चुर्क सीमेंट फैक्टरी में तब तक लासाचलर्ता रहा जब तक आई०ए० एस० अफसर वहां के चेयरमैन होते रहे । जब वह परिपाटी बदली गयी तब वह फैक्टरी मुनाफे में चल सकी । कोई भी कंसर्न हो उसमें वह फिट हो सकता है । वह डिप्लोमैट हो सकता है भले ही डिप्लोमेसी का उसे कोई ज्ञान न हो, लेकिन उसके बावजूद भी नये स नया आई० ए० एस० अफसर डिप्लोमैट हो सकता है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): You will have to wind up.

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही: और जैसा कि हमारे मित्र चक्रवर्त्ती साहब ने कोट किया, हर तरह से प्रशासन की सहूलियत के लिये और प्रशासनिक ढांचे को ठीक करने के लिये आवश्यक है कि हर कैडर के लोगों को अपने अपने रास्ते पर आगे चल कर उच्चतम स्थान पर पहुंचने का अवसर मिलना चाहिए ।

वैज्ञानिकों के संबंध में निर्णय लेना हो तो उस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी वैज्ञानिक होना चाहिए, मेडिकल के संबंध में कोई निर्णय लेना हो तो उस डिपार्टमेंट का हेड कोई मेडिकल अफसर होना चाहिए। इसी तरह से इंजीनियर्स के संबंध में कोई निर्णय इंजीनियर्स को ही लेना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि जो नया संशोधन विधेयक आयेगा उसमें इसका ध्यान रखा जायगा।

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA (Orissa): Mr. Vice-Chairman, Sir, in moving this Bill for the consideration of the House, Dr. Chakrabarti intends to highlight the problems of administrative reforms. He wants that the problem of giving appropriate opportunity to scientists and technologists for reaching the higher order of administration which they so richly deserve be considered. He also wants the problem of keeping open the top posts in administration for our scientists and technologists to enable them to participate effectively at the policy and the decision making levels to be considered.. To achieve these two objectives, the solution provided by him is that lateral entry from other services to the top decision-making position in every sphere of our administration and managerial work should be provided. Keeping all these things in view, he has moved an amendment to article 312 of the Constitution. He wants that a new clause should be inserted in article 312. Sir. I would respectfully submit that though I had no quarrel with the sentiments expressed by Dr. Chakrabarti about the discriminatory treatment given to the scientists and technologists and the importance given to the officers of the Indian Administrative Service, I feel that the Bill itself is redundant and misconceived. If you kindly refer to article 312, the point that I am making will be absolutely clear to you, Sir. Article 312 says:

"Notwithstanding anything in Part XI, if the Council of States has declared by resolution supported by not less than two-thirds of the members present and voting that it is necessary or expedient in the national interest so to do, Parliament may by law provide for the creation of one or more all-India services common to the Union and the States..."

You will kindly see, Sir, this article 312 of the Constitution is an enabling article. If at any time it is felt necessary or expedient in the national interest to create an all-India service, such a service can be created by a certain procedure laid down under article 312, first by a resolution supported by not less than two thirds of the members present and voting in the Rajya Sabha, and then by bringing forth the necessary legislation. Therefore, I do not find any necessity for adding a new clause which Dr. Chakrabarti seeks to add. And I feel that the necessity of creating any all-India service can be fulfilled by the existing article itself. So, my first point is that this amendment is absolutely redundant, it is not necessary. Even without his amendment, the purpose of Dr. Chakrabarti's amendment can be served provided it is felt expedient and in the national interest to create an all-India service of the nature contemplated by Dr. Chakrabarti. Sir, his ideas are laudable and I also share some of the sentiments expressed by him to give due importance to scientists and technologists. Though he began with a bang, practically the whole things ends in a whimper because the very introduction of this Bill is absolutely unnecessary.

Then, Sir, the solution given by Dr. Chakrabarti is that lateral entry from other services to the top decision-making positions in every sphere of our administrative and managerial work should be allowed, and then only this discrimination will go. This is the solution given by him. I would submit that the Administrative Re-

[Shri Narasingha Prasad Nanda]

'orms Commission, *vide* the report of its Study Team on recruitment and selection by UPSC and State PSCs and training, accepted this principle. They had recommended this principle. You will find their recommendation on this point at page 16 of this report. About the lateral entry they said:

> "One of the methods of improving the quality of a cadre is to induce highly qualified persons to its higher levels. Such lateral entry at the higher levels is usually opposed by the service interests concerned on the ground that it affects adversely the prospects of promotion and as a result lowers morale. While we would not belittle this objection, we consider that at least in the technical services and in posts requiring specialists qualifications or experience, limited provision for lateral entry will be all to the good of the public service."

This was the recommendation of the Team which was appointed to study this question of recruitment, selection, etc., by the U.P.S.C. and the State Public Service Commission. So, the principle of lateral entry was accepted on the basis of this recommendation of the Administrative Reforms Commission and, to some extent, this lateral entry was allowed. In fact, I have personal knowledge that in some of the States the Secretaries or heads of Departments are technologists for instance, in my State the Chief Engineer is the Secretary in the Ministry of Works. Though he is a technocrat he has been made the head of a department, in order to experiment with this principle of lateral entry and seeing how far this can be extended to various other services. Therefore, the question is to what extent the recommendation of the Administrative Reforms Commission accepting the principle of lateral entry from other services into the all-India services, can be implemented? The question therefore is what should be the proportion of technocrats and scientists to be accommodated in the top-ranking positions, in the policy-making positions of the Government both at the Centre and in the States. As I said at the outset, it is essentially a problem of administrative reforms and this reform can be tackled without amending article 312 of the Constitution. Article 312 is only an enabling article and it lays down the procedure. If you find it expedient to create an all-India service in the national interest, then you must pass a resolution by two-thirds majority here and then bring forth legislation and create an all-India service. In fact, in the beginning we had only the Indian Administrative Service and the Indian Police Service. But, now we have got the Indian Forest Service, the Indian Medical Service, the Indian Engineering Service and the Indian Economic Service. We have also got the Indian Statistical Service. As and when we feel the need for creating an all-India service, we can do it. Article 312 is a self-contained provision. Where is the scope for bringing forth such an amendment to it? That is why I say, however, laudable the idea may be, and even though I may be sharing some of the sentiments expressed by Dr. Chakrabarti, this amendment is redundant, is absolutely unnecessary, and even without bringing forward this amendment the purpose sought to be achieved by Dr. Chakrabarti, can be achieved. Of course, I must express my thanks to Dr. Chakrabarti because he has given us an opportunity to state our views on this matter and when such an occasion has been created he has not only enabled me to speak but also enabled other Members also to speak on anything under the Sun, which is the tradition of our speeches. In utter disregard to the relavance of the subject matter we can talk on anything under the Sun, that is a privilege we have got and that is a sacred privilege which must be preserved at any cost.

On principle, I accept what Dr. Chakrabarti says. His reasons are acceptable and I agree with his ideas but I am not prepared to agree with him on this amendment because my argument is that it is redundant and is not necessary. Article 312 is self-contained and it will solve his problem. Thank you.

SHRI JAGAN NATH BHARDWAJ (Himachal Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, I congratulate Dr. Chakrabarti for the reason that it is a very important issue. There is a controversy between the I.A.S. and other services in the country, controversy between the technocrats and the I.A.S. and this question is becoming very important because it is affecting the roots of our administration and it is cause of great heart-burning among the technocrats in the country. So, I must congratulate Dr. Chakrabarti for raising this important issue.

We have seen at the lower levels, for example, in the district administration, the engineers and other technocrats, the forest officers and others sometimes grumble that these I.A.S. officers are not treating them well and that they develop a sort of inferiority complex before the I.A.S. officers and on the other side, the I.A.S. officers behave like bosses over other services. This sort of discontentment is weakening the roots of our administration at the district level. At higher levels also, we have seen that the technocrats always grumble and complain that all these bigger posts are given to I.A.S. officers and the technocrats are ignored with the result that advancement in the field of science and technology is hampered due to this growing discontentment. It is, therefore, apparent that a sort of controversy or confrontation between the I.A.S. and the technocrats is developing in our country. It is high time that something is done to solve this controversy or to minimise this heart-burning and discontentment amongst the various services in the country. Therefore, as Dr. Chakrabarti suggested, it is possible that at higher levels, a service as Indian Administrative and Managerial service can be developed or some other name can be given to this new service. It is necessary that at levels above the junior posts, for example, the level of Junior Engineer or the Sub-Divisional Officer,—up to this level, the technocrats and administrative people can work without any difficulty. At the divisional level, for example, the Deputy Commissioner's level or the level of Executive Engineer, both the technocrats and the administrative people should be merged into one common service so that this growing discontentments is minimised. This is not a new thing. In the Army we have got this practice. For example, above the rank of Major, they send all people to the Administrative Staff College. They get some training before they become Colonels. They get a sort of training there in the Administrative College. Above that level, all are eligible for higher positions. He may be a medical man, he may be an engineer or an officer in the fighting forces. I think some such system should be there. Of course, they may not reach the top. As far as my knowledge goes, there has been no case where an engineer has reached the position of a commander, supreme commander. But still, they go to sufficiently high levels so that there is very little cause for discontent in the Army. This practice of giving chance to all services is there in the Army. I think the same practice should be followed in the case of the civil services also. When selections are to be made at the divisional level and above, due representation should be given to the technocrats so that they could occupy top administrative and managerial positions. This will make them feel that they are not subordinates and this will also enable them to develop their skill and technology. This will also arrest the superiority complex growing in the minds of the administrative officers, I.A.S. officers. I think, some sort of a balanced arrangement is absolutely essential.

With these words, I support the Bill which has been moved by Dr. Rajat Kumar Chakrabarti.

SHRI NRIPATI RANJAN CHOUDHURY: Sir, Dr. Chakrabarti has been agitating on the floor of this House since 1972 for the betterment of the lot of the technocrats in the country. He was with us till the other day. Now he has crossed the floor.

DR. RAJAT KUMAR CHAKRABARTI: I have not crossed the floor.

SHRI NRIPATI RANJAN CHOUDHURY: He has left us.

DR. RAJAT KUMAR CHAKRABARTI: You can say I have left you. You cannot say I have crossed the floor.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): We do not know who has left whom.

SHRI NRIPATI RANJAN CHOUDHURY: He is still continuing his agitation for the technocrats.

SHRI KALYAN ROY (West Bengal): Sir, there is no quorum.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): We generally carry on.

SHRI NRIPATI RANJAN CHOUDHURY: Last of all, he wants to put the things on record and, therefore, he is here with this Bill. He knows quite well that the Government is not going to accept this Bill. But he wants to highlight the grievances of the technocrats.

DR. RAJAT KUMAR CHAKRABARTI: How does the hon. Member know that the Government is not going to accept this Bill?

SHRI NRIPATI RANJAN CHOUDHURY: The Government is not going to accept it.

DR. RAJAT KUMAR CHAKRABARTI: He is not a mind-reader.

SHRI NRIPATI RANJAN CHOUDHURY: He is also not a mind-reader. The Minister is there. He is there to say whether he is going to accept it or not.

Dr. Chakrabarti has raised the point in favour of the technocrats occupying higher positions in Government departments. Sir, there has been a countrywide agitation. There is still a countrywide agitation by the technocrats against the I.A.S. overlordship. The technocrats throughout the country feel that proper justice is not being done to them and that the I.A.S. officers are trying to keep them subservient. This is because it is the I.A.S. officers who are at the helm of affairs in the administration and it is they who advise the Government. Therefore, the Government is not prepared to improve their lot. Sir, this feeling is further accentuated by the recent decision of the Government of India, to take out the research laboratories from the CSIR. So long, these scientists in this country were conducting their research work under the control of the CSIR, they were taking decisions for themselves, they were giving a lead to the scientific and industrial research, but now the CSIR is killed and the scientists will be completely under the control of the administrative officers, under the IAS people, and it is the IAS people who will guide the scientific and industrial research in this country. With this state of affairs, Sir, you can imagine the fate of this country.

Under these circumstances, when Dr. Chakrabarti comes before this House with this Bill, I welcome the very intention of Dr. Chakrabarti. Whether I support the Bill or not comes later, but I welcome his intention or the very object of the Bill. In the Statement he has suggested that the powers of the IAS officers should be cut.

Now, Mr. N. P. Shahi, while speaking on this Bill, said many things and not only Mr. N. P. Shahi but most of the members of the Janata Party and the present Government are suffering from 'Indira' fever. Whenever anybody stands from that side to speak, he brings in Indira Gandhi and sometimes he will also bring in Sanjay Gandhi.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): I thought Mr. Shahi was supporting Mrs. Indira Gandhi.

SHRI NRIPATI RANJAN CHOUDHURY: Not only supporting, but they are suffering from that fever. So, everytime the name of Indira Gandhi must come in, the name of Sanjay must come in. The other day, you know when my Bill was under consideration, the Law Minister while replying dealt with Indira Gandhi and Indira Gandhi alone for more than 45 minutes and 10 minutes on my Bill. He also referred to the dissolution of Lok Sabha and what would have happened to Mrs. Gandhi had Lok Sabha been dissolved, forgetting that if my amendment was accepted, a specific provision could have been made for an interim government to meet with such situation. But their mind is pre-conditioned with Indira Gandhi. They are suffering from that fever. Everywhere they see Indira Gandhi, Indira Gandhi and Indira Gandhi and nothing else. So, Sir, while discussing a problem of the technocrats, while discussing an agitation by the technocrats against these IAS lords, there also this name of Indira Gandhi is brought in. In all discussions the name of Indira Gandhi, the name of Sanjay Gandhi and everyone else should appear. I am not going to answer to all these things which he has referred to, but my point is that he also said as to how IAS people have become very powerful. He also said that he wants to put these things on record so that this new Government does not fall a prey in their hands again. Sir, why has this power accumulated in the hands of the IAS? It is because we attach a lot of importance to the IAS Officers. Wherever a question of manning some industry or concern comes in, you put an IAS officer. We do not apply our mind in that way as to what type of people should be selected for what purpose. Yes, put an IAS officer there that is our approach. If a municipality is not being run properly, put an IAS officer as Administrative Officer. Whatever it may be—whether it is industrial research or scientific research—put an IAS officer at the helm of affairs. Without being scientists, they will conduct scientific research in this country. Sir, this is the *motivation*. And this motivation is the result of 200 years of colonial rule. Sir, in this country the whole motivation of the IAS cadre is modelled on that of ICS officers. What was the ICS model? It was to rule and loot. The British people were not interested in the development of this country in any field—scientific, industrial or economic. What were they interested in? They were here to loot and rule, to rule to loot and not for anything else. They had to rule us. They ruled us to loot. And this very model we have adopted. Sir, today if one has to appear for an IAS interview, one cannot appear in *dhoti* and *kurta*. One must be a suited-booted man. One must speak Queen's English, not Asian English or Indian English. Sir, I want to put a simple question to the Minister through you. Has he ever seen a single IAS officer Wearing *dhoti* and *kurta*? Has he ever seen two IAS officers addressing themselves in any Indian language? So these are his qualifications. Why a candidate going to appear for IAS interview dare not wear *dhoti* and *kurta*? Because the mind of those who sit on the board of interview is....

SHRI KALYAN ROY: Poisoned.

SHRI NRIPATI RANJAN CHOUDHURY: Not poisoned but their mind is absolutely so modelled that they are not prepared to accept an Indian in the cadre. So it is a new Anglo-bunglo, anglicised Indian society that they are going to build in this country. And at the top of it, they have to rule, they have to dominate. So, Sir, the first thing that we or Dr. Chakrabarti wants to fight is this IAS domination over the administration. This must go and for that the Administrative Reforms Commission has also suggested that effort should be made for lateral entry to the highest posts from the different cadres. Dr. Chakrabarti's real intention is also

[Shri Nripati Ranjan Choudhury]

that engineers, doctors, scientists etc. should be given scope to go up to the level of Secretary at the Centre and also in the States. Sir, it is really painful. The other day, I was travelling with an Indian Forest Service officer. We were discussing about the prospects of IFS officers *vis-a-vis* IAS officers. He also said that they could go up to the post of Chief Conservator of Forests in the State and there was only one post in the country of Inspector-General of Forests. So they have to stagnate at the post of the Chief Conservator of Forests in the State. In calibre and qualifications they are no inferior to an I.A.S. officer. Therefore, if things continue to be in that shape for long all these people will revolt. If the technocrats in this country feel that they are to rot only do you mean that any development will take place in this country? So it is in the national interest that the power of I.A.S. should be curbed and scope should be extended to all the technocrats to become at par with the I.A.S. officer at the top. By his amending Bill Dr. Chakrabarti wants that Parliament may by law provide for the creation of an All-India Service. He wants to create another all India service, Sir, called Administrative and Management Service taking men from all the cadres, technocrats, scientists, medical men, and also men from State services. Sir, I speak subject to correction, I think this will create further complicacy because somebody is an engineer, somebody is a medical man, somebody is a scientist and somebody is from Forest Service and somebody is from some State cadre. Bringing men from different groups in one unified service, Sir, I think will create further complicacy. Posting of men will be creating further complicacy. The purpose can be served by the example followed in my home State. For instance, in my home State an Engineer can become the P.W.D. Secretary, the Irrigation Secretary or the Flood Control Secretary. We can make room for the technocrat in the Secretariat without amending anything, without creating a new service.

Secondly, even what Dr. Chakrabarti wants to do by this amendment can be done without this amendment. Sir, Article 312 of the Constitution says:

> "Notwithstanding anything in Part XI, if the Council of States has declared by resolution supported by not less than two-thirds of the members present and voting that it is necessary, or expedient in the national interest so to do, Parliament may by law provide for the creation of one or more all-India services common to the Union and the States, and, subject to the other provisions of this Chapter, regulate the recruitment, and the conditions of service of persons appointed, to any such service."

Sir, this Article empowers the Rajya Sabha to adopt a Resolution to the effect by a majority of two-thirds present and voting, and if this Resolution is adopted by the Rajya Sabha then Parliament by law can do that without amending the Constitution. So, Sir, while at the beginning of my speech I said that the Minister may not accept it, but even if the Minister does not accept the amendment, the Government can take steps so that the object for which Dr. Chakrabarti moved this Bill can be achieved. And I believe, Sir, persons speaking from the Janata Party side also supported the amendment. The Minister may not accept the amendment but he can be of one opinion with us all that something should be done for the technocrats so that they can come up and rise to the highest positions available to the IAS people.

With these words, Sir, I conclude. Thank you.

SHRI KALYAN ROY: Sir, I will be brief. I do think that the Bill is of vital importance to the country and the Government should give serious consideration to the intention and purpose of the Bill.

Sir, it is true that once Pandit Jawaharlal Nehru said, in relation to the Indian Civil Service, that it was neither Indian nor civil nor service. But, after independence, the past Government did not dare to touch them and rather kept them as they were with all their privileges, positions and salaries--which is a matter of shame. We were never reconciled to the special status given to the ICS. As a matter of fact, if one goes through the proceedings of the Constituent Assembly, one finds a large number of Congress members who protested against giving an extra-special position to the ICS officers. But both Mr. Patel and Mr. Nehru succumbed and agreed to have them, although it is also true that they did not, at least, give the Indian ICS officers the facility to opt for pension. All these are now matters of history.

Sir, what we saw in that period, at the beginning of the 20th century, was that the ICS did produce some brilliant people who contributed to history, culture, science, music, archaeology and so on. Their numbers became few later on as the national liberation movement grew, and as the movement gathered strength and the masses started to move, the entire ICS was mobilised to suppress the movement. One of them was Mr. B. R. Sen.

Sir, you are aware that in the Midnapore district, in the 1930's, three European Magistrates were murdered one after another. The first was Mr. Pady, the second, I think, was Mr. Douglas, and the third was Mr. Burge. And this terrified all the English officers. No ICS officer dared to go to Midnapore. Then the alternative they found was the stooge, Mr. B. R. Sen. To our great shame and sorrow, the same Mr. B. R. Sen was promoted by the Government led by Nehru, led by Lal Bahadur Shastri, led by Indira Gandhi. They kept the structure intact, a structure which was meant to exploit people, to suppress the national liberation movement. One of them, I remember, is Mr. Dharma Vira who was made a Governor. And his first contribution was to create lawlessness in West Bengal when the United Front Government took over power. He dismissed that Government illegally and the people gave their verdic by returning the United Front to power in 1969 with an overwhelming majority.

Dharma Vira had to go and this man, pigmy of a man, ultimately sought shelter in one of the biggest monopoly houses, Bharat Ram, Charat Ram. They gave him a job and he was connected with the Bengal Potteries, which, thanks to the brilliant mismanagement by Bharat Ram, Charat Ram, was closed down after misappropriating Rs. 3-4 crores from IRCI—and one of the partners was Shri Dharma Vira. In any other country perhaps they would have been in jail today. But, then, after all, what is the difference between the Government led by Mrs. Gandhi and the Government led by Mr. Desai? The same Dharma Vira has been appointed, as far as I know, the Chairman of the Police Commission. So, the attitude is the same, the look-out is the same and the policy is the same, whatever may be the intention of Dr. Rajat Kumar Chakrabarti.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. RAM KRIPAL SINHA): You support him.....

(Interruptions)

SHRI KALYAN ROY: I expect more courage from him. Here is the man who in this very House, when he was not a Minister demanded why the Government was taking so much time to dismiss the officers connected with Chasnala. And today I saw, to our shame, that he did not open his mouth He is a courageous man. I do not want to deviate. These things do happen when a man becomes a Minister. I have full sympathy with him that he should be promoted to the Cabinet rank.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Mr. Kalyan Roy, this is the penalty one has to pay when one becomes a Minister.

SHRI KALYAN ROY: Sir, the attitude is the same. When the British left and the word 'ICS' was not liked by the people as a whole, they set up this organisation called the Indian Administrative Service, which the IAS officers jokingly call the 'Indian Automatic Service. Whether you are efficient or not, whether you are dynamic or not, whether you are capable or not, your promotion is assured. Have you found in the last 30 years any cases—there may be one or two cases—of dismissal of IAS officers for their failure to carry out their duties properly? You will be surprised, Sir, that an officer connected with the gang of Bansi Lal was responsible for atrocities in Haryana and he was recommended to be punished and the Haryana Government, I think, took some steps in that direction, but then the Central Government intervened and he was kept in his old position in Chandigarh. This is how the powerful structure operates. Nowhere in the world do you find this. All officers, either the District Magistrates or the Sub-Divisional Officers or the Secretariat Officers, have to come from the bottom.

Another thing is that when we send abroad a Government delegation for technical collaboration the leader of the delegation is a man who knows nothing about the technical part of it—the job is done by others—while those who represent delegations from abroad are the topmost authorities in the field. That is the whole tragedy.

The year before last, a Soviet Union Minister, Mr Bretchenko an outstanding authority on coal-mines, was talking with Mr K. C. Pant, who has been underground once in life and who would not be able to distinguish between coking coal and noncoking coal That is the whole structure The reason why I am raising the issue is that, whether in Administration or in the Cabinet, persons who have not specialised in anything are promoted. I know that in a parliamentary form of government you cannot have all the technocrats sitting on the Treasury Benches. But at least there should be some specialists. That is not there.

And this IAS structure which has become so gigantic, so powerful and so big, is one of the stumbling blocks for a radical transformation of the society. After all, what are we for? Do you want a radical transformation or not? Do you want the *status quo* to remain? If we want the *status quo* to remain, then the IAS must remain there, we should not disturb it.

What is the education they get? They go to Simla. As one Hon. Member pointed out, these people are drawn from the upper-middle class, middle class, rich gentry or the elite, and none from the working class, they cannot afford. All these people are grouped together and are made *sahebs*. They are first taught to wish good-morning to each other, how to handle the fork and knife—not that they learn anything—to distinguish between an omelette and a fried egg. Then they go for lunch, then afternoon tea at four early dinner, midnight cap and then they go to sleep. These are the things which they are taught very meticulously. Unless they know these things, the Government feels and the Government felt before that they would not be able to administer a particular thing. People must be afraid of this new class The whole purpose is and the whole psychology is so built that the people as a class are separated from officers. That is why I have complained that in my areas and also elsewhere, nowhere have I seen an IAS officer going to *dhoura*, a worker's quarter or a Harijan *basti* and sharing his meals with them. The IAS officers' gates are always open for the tycoons of the area, the blackmarketeers, the transport operators or the businessmen. Sir, I can give an instance in Asansol. A few years ago private

mine-owners were there, IISCO authority was there and even now there are big industrialists there. I personally once asked a worker to go and invite him. The worker was not allowed to enter the bungalow of the officer. This is the world we are living in. It is a tragedy. I will not blame the Janata Government for it. This is a structure which was built up by the past Government, it has been kept intact by the present Government, and I do not feel at all that they would disturb it. The same officers who were briefing Mr. Pranab Mukherjee are now briefing Mr. Patel. The same officers who were briefing Mr. K. C. Pant, are briefing Mr. Ramchandran. I do not see any change, neither have they any intention to change the pattern. They think that without the IAS the whole administration will collapse. I strongly dissent. We have brilliant people down below, people who need promotion, who have dynamism with legs rooted to the earth, the ground. Their future is blocked. They cannot go up. Few are being promoted. But an IAS officer automatically becomes SDM, then DM, then Under Secretary, then Deputy Secretary, then Joint Secretary and then Secretary.

I know, Sir, one instance in the Coal Department of the Ministry of Energy. Of course, that gentleman has retired two days' back. Mr. Chari who was the Secretary of the Coal Department, Ministry of Energy, was the first non-IAS, non-ICS officer to become a Secretary of a Department, and he actually had to face hostility everyday. They were thinking that there was a non-IAS man and that their privilege had gone.

The whole *status quo*, our mixed economy, our monopoly houses and our IAS officers are tied together. Dr. Chakrabarti is there. He sees only one part of it. But this whole thing is there, this colonial structure which we inherited etc., and not only the IAS. Even if you remove all the IAS and have the technocrats everywhere, the exploitation, the poverty and the really sordid conditions will all continue.

Technocrats alone do not improve the situation. I was surprised today to read a press statement by one of the very leftist Ministers of the present Government in West Bengal, Dr. Jatin Chakrabarti. He said "In some of the public sector undertakings of the West Bengal Government, technocrats are at the top, but they have ruined the public sector undertakings there". I say, this is a part of the whole exploiting system which has been built over the years and which has gained strength. It is not easy to fight with them. Already you have seen in the papers that in State after State, there have been conflicts and clashes between the Janata Ministers and the IAS officers. Somewhere the IAS officers had to retreat and somewhere the Ministers had to retreat, as in Punjab. Mr. Charan Singh also had written an article in the *Illustrated Weekly* or somewhere, I remember. These conflicts are bound to grow and they will be there because the IAS officers think "Well, Ministers may come and Ministers may go; after all, we are the bosses." And with the present composition of the Government, more people are inclined to think so—how long this Government will last, or how long this party will last? This party may break up into fragments and the sooner it does, the better it is for the country. (*Time bell rings*). The question is: Do they have the intention to fight this super-structure which has been built? It has to be fought out. If it is not fought out, it will mislead the Government today as it tried to mislead the Government yesterday. I do not say the bureaucrats alone are responsible for the evils of the Emergency. The Government at that time was equally responsible. It is no use blaming the bureaucracy alone. I blame Mrs. Gandhi; Mrs. Gandhi was equally responsible. But the bureaucrats also played a large part. But if this Government at all wants to do something good, my suggestion is this. Not that they have not done anything

[Shri Kalyan Roy.]

good. I do agree that at least they have restored democracy. There is no doubt about it, and I congratulate the present Government for that. But that is certainly not enough. If there is no political censorship, is it not correct that all the exposures of the offences by the big monopoly houses are suppressed from the papers? We discussed that day the foreign exchange violations by Mr. Hayward of Shaw Wallace and Company. We discussed about how the house of Goenkas is looting the tea gardens. We discussed the affairs of Bird and Company. All these were shut out from the press because the press is dominated by persons like Tarun Kanti Ghosh, who has joined the Janata Party, or Ramnath Goenka or K. K. Birla of the *Hindustan Times*. So, though the political censorship, the naked, crude censorship has gone, the invisible financial censorship continues. So, I do not think this Government will accept the suggestion. Dr. Chakrabarti asked "How do you know they will not accept it?" They cannot accept it because they are also tied with the *status quo* like the past Government. They do not want to disturb the *status quo* and for the *status quo*, the IAS officers are a "must". But if they want to radically transform the society, to distribute land to the landless to consider seriously abolishing the system of monopoly, to bring about dynamism in this country which is today drifting apart here and there, then they must think in terms of a new administrative structure and a new type of thinking should come in their mind, so that jointly we can go forward together and this unnecessary conflict and suspicion between the IAS officers and the rest will vanish for ever. Thank you.

श्री कल्पनाथ राय (उत्तर प्रदेश) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं डा० रजत कुमार चक्रवर्ती साहब ने जो यह संशोधन प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करता हूं। आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान की आजादी के बाद आज 30 वर्षों के बाद या बीच में कई बार ऐसी व्यवस्था बनी है कि प्रथम कोटि के राजा तो बदल जाते है लेकिन दूसरी कोटि के जो देश को चलाने वाले लोग हैं वे नहीं बदलते है यानी 9 प्रान्तों में 1967 में गैर कांग्रसी सरकारें भी बनी और आज तो केन्द्र में जनता प्रार्टी की सरकार बनी है, ऐसा अन्य दुनिया के देशों में नहीं होता है। अमरीका में अगर रिपब्लिकन पार्टी की हकुमत कायम होती है या डेमोक्रेटिक पार्टी की हकुमत कायम होती है तो जो राष्ट्रपति होता है वह क्राम टाप, 10000 एक्जीक्यूटिव आफिसर्स का नया एपाइंटमेंट करता है, अपनी नीतियों को चालू रखने के लिए, चरितार्थ करने के लिए या लागू करने के लिए। अथवा प्रेजीडेंट, जो एक्जीक्यूटिव हेड होता है उसे 10,000 टाप एपाइंटमेंट करने की पावर होती है। लेकिन हमारे मुल्क में आजादी के साथ जो सिस्टम आया वह साम्राज्यवादी था। नौकरशाही का जो साम्राज्यवादी रूप था उसी को हमने ग्रहण किया। इसके अलावा जब तक इस देश की शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन नहीं होगा, जब तक पांच प्रकार के स्कूल रहेंगे, पांच प्रकार की किताबें रहेंगी, पांच प्रकार के अध्यापक रहेंगे तब तक लोकशाही, समाजवाद और नौकरशाही की बात करना बिल्कुल बेकार है। अगर हमें इस मुल्क की नौकरशाही में बुनियादी परिवर्तन करना है तो हमें इस मुल्क की शिक्षा पद्धति में आमूल-चूल परिवर्तन करना होगा। शिमला, ऊंटी, देहरादून और दून के कालेजो में जो लड़के पैदा होंगे वह कभी भी हिन्दुस्तान की 50 करोड़ गरीब के जनता के प्रति वैसा व्यवहार नहीं कर सकते है। इसलिए हमें नौकरशाही के ढांचे में आमूल-चूल परिवर्तन करना होगा और जब तक शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन नही होगा तब तक हिन्दुस्तान की नौकरशाही के ढांचे मे कोई परिवर्तन हो नहीं सकता है। आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हम जब कभी आई० ए० एस० आफिसर से मिलते हैं तो वह भी

आज यही महसूस करता है कि उसकी कोई हैसियत नहीं है। आई० ए० एस० आफिसर भी सबार्डिनेशन महसूस कर रहे है और जब जनता के प्रतिनिधियों से बातचीत होती है तो वे भी यही कहते फिरते हैं कि आज नौकरशाही की हकूमत है, हम तो कुछ नही हैं। आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इस देश की राजनीति मे एक तरह से दो प्रकार की पीड़ा की स्थिति पैदा हो गयी है। हिन्दुस्तान का आई० ए० एस० आफिसर भी अच्छा महसूस नही कर रहा है। आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय,

A civil servant is just like a horse

एक सरकारी कर्मचारी एक घोड़े के समान होता है यदि घोड़े पर सवारी करने वाला बढ़िया है तो जैसे ही पहली एड़ लगाकर घोड़े पर सवारी करेगा, वैसे ही घोडा अपनी गति मे ठीक चलेगा। लेकिन अगर घोड़े को यह पता चल जाय कि उस पर सवारी करने वाला बिल्कुल बेवकूफ है, उसे कुछ नही हो सकता है तो वहीं पर घोड़ा उस सवार को उठाकर पटक देगा। आज हमारे देश की नौकरशाही अगर ठीक ढग से काम नहीं कर रही है तो उसका यही कारण है कि जो उस पर सवारी करने वाले लोग हैं वे उतने योग्य नहीं है जैसे कि होने चाहिएं। आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक बात साफ कहना चाहता हूं कि इस जनता सरकार मे आज हमारे प्रदेश में ऐसा मुख्य मंत्री बनाया गया है जिसको कि सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी या एडीशनल सेक्रेटरी मे क्या फर्क है, इनकी पावर में क्या फर्क है, इसका भी ज्ञान नही है, जिसको प्रशासन का क, ख, ग, भी नहीं मालूम है। जनता पार्टी में बहुत अंदरूनी संघर्ष हैं, अपनी राजनीतिक सत्ता के कारण यह मेरा है यह मेरा नही है, इसके कारण उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को मुख्य मंत्री बनाया है जो कि एक तहसील को भी नहीं संभाल सकता है परन्तु उसको 10 करोड़ पापुलेशन का दायित्व दे दिया और फिर यह कहते हैं कि आई० ए० एस० आफिसर ठीक नही है, यह नौकरशाही ठीक से काम नही कर रही है, हम बहुत काबिल है। परन्तु ऐसी बात नहीं है। हिन्दुस्तान के नेता के मन मे एक बात साफ होनी चाहिए कि हिन्दुस्तान की जो नौकरशाही है वे भी देश के नागरिक है; आई० ए० एस० आफिसर भी इस देश के सिटीजन हैं। आप अपनी नीतियों मे परिवर्तन नही करेंगे और दोष नौकरशाही को देंगे। और देश की नौकरशाही के लिए देंगे। मै कहना चाहता हूं, आज हिन्दुस्तान की जो बुनियादी बीन है, हिन्दुस्तान का प्रशासन चलाने की जो क्षमता है, वह हिन्दुस्तान की नौकरशाही के कारण इस देश का शासन चल रहा है। हमने क्या अपनी शिक्षा नीतियों मे परिवर्तन किया, क्या हमने अपनी बुनियादी सर्विस नीतियों मे परिवर्तन किया, क्या हमने अपनी नीतियो में आमूल-चूल परिवर्तन किया ? लार्ड मैकाले ने जो अंग्रेजी साम्राज्य-वाद के सबसे बड़े लम्बरदार थे, उसने अपनी किताब मे लिखा है :

We must do our best to form a class which may be interpreters between us and the millions whom we govern—a class of persons Indian in blood and colour. English is just an inteliect....

"हिन्दुस्तान को गवर्न करने के लिए हमें एक ऐसे क्लास का निर्माण करना है जो हम अंगरेजों और हिन्दुस्तानियों के बीच में इन्टरप्रेटर का काम कर सके"। लार्ड मैकाले की शिक्षा-प्रणाली ही आज हिन्दुस्तान में कायम है और इसी शिक्षा-प्रणाली के कारण ही हिन्दुस्तान में नौकरशाही भी पैदा हुई है और जो ढांचा अंगरेजों ने दिया, क्या उसको इस देश का आइ० ए० एस० आफिसर बदलेगा? क्या आइ० ए० एस० आफिसर उस ढांचे को बदलने की क्षमता रखता है। यह देश का शासन चलाने वाले लोगों की जिम्मेदारी है कि वे मुल्क के ढांचे में परिवर्तन करें—जो इस मुल्क की नौकरशाही के ढांचे में परिवर्तन करे, जो इस मुल्क की शिक्षा-पद्धति के ढांचे में परिवर्तन करे जो इस

[श्री कल्पनाथ राय]

मुल्क की सामाजिक और आर्थिक नीतियों में परिवर्तन करे और वही इसी मुल्क को चलाने की शासन-पद्धति में परिवर्तन करे। आज हिन्दुस्तान के राजनैतिक जीवन में जिस ढग की गिरावट आ रही है उससे ज्यादा आइ० ए० एस० आफिसरों में गिरावट नहीं आई है। आई० ए० एस० आफिसर कोई अंगरेज नहीं हैं, ये आइ० ए० एस० आफिसर अपने देश के रहने वाले हैं, अपने ही मुल्क के नागरिक हैं, वे भी इस मुल्क के प्रति सोचते हैं समझते है लेकिन किस ने उनको यह अधिकार दिया है? हमने दिया है, हमारे देश के राजनैतिक तंत्र ने दिया है या यह आइ० ए० एस० आफिसरों ने दिया है? इसलिए आइ० ए० एस० आफिसरों को दोष देना कि ये जिम्मेदार है हिन्दुस्तान की गड़बड़ियों के लिए, यह गलत है। यह देश के जो नेता हैं, जो इस देश को चलाने वाले लोग हैं, वे इस देश की नीतियों में परिवर्तन करें। फिर यदि वे उस परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं तो उनको गलत कहा जा सकता है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, धर्मवीर को पुलिस कमीशन का चेयरमैन क्यों बनाया है। ऐसे लोगों को मंत्री बनाया जाता है जिनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है। इसमें किस का दोष है? जिस व्यक्ति को बिधान सभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखने का ढंग नहीं है, जिसको अपनी विधान सभा में खड़ा होने का ढंग नहीं है, जिसको अपने प्रदेश के भूगोल और इतिहास का ज्ञान नहीं है, उसे आपने मुख्य मंत्री बना दिया और वहां कोई सिंचाई योजना नहीं चलेगी, वहां कोई कृषि उत्पादन का कार्य नहीं होगा, उस प्रदेश में कोई इंडस्ट्रियल और अग्रिकल्चरल डेवलपमेंट नहीं होगा, तो क्या इसके लिए नौकरशाही जिम्मेदार है? नौकरशाही को बिना कारण गलत कहना यह भी बड़ी गलत बात है। इसलिए पहले हमको देश की शिक्षा-पद्धति में आमूल परिवर्तन करना चाहिए, दूसरे, जब सत्ता में परिवर्तन हो तो सत्ता में परिवर्तन के साथ 1000 या 2000 जो टाप एक्जीक्यूटिव्जम है, उनमें भी परिवर्तन होना चाहिए। अपने मुल्क की शिक्षा-पद्धति में आमूल परिवर्तन करके हमें नयी नौकरशाही का निर्माण करना चाहिए।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आज हिन्दुस्तान इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और टेकनोलाजिकल रिवोल्यूशन के दौर से गुजर रहा है इसलिए यह देश के नेताओं का कर्तव्य है कि वे टेकनोक्रैट्स को सेक्रेटरी नियुक्त करें। अगर बिजली बोर्ड है तो उसका चेयरमैन कोई इन्जीनियर हो, उसका सेक्रेटरी भी इन्जीनियर हो। कौन किसी मुख्य मंत्री को कौन प्रधान मंत्री को किसी टेकनोक्रैट को यू० पी० एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का चेयरमैन बनाने से रोकता है? यह तो मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री का डिस्क्रेशनरी पावर है; यदि वे चाहें तो किसी टेकनोक्रैट को यू० पी० इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का चेयरमैन बनाएं, किसी टेकनोक्रैट को यू० पी० इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का सेक्रेटरी बनाएं। यह तो राजतंत्र में जो देश को चलाने वाले लोग हैं उनके ऊपर मुनहसिर करता है। तो मेरा कहना है कि हमारे देश के अन्दर आइ० ए० एस०, जो जर्नेलिस्ट्स है, उनके ऊपर टेकनोक्रैट्स को, स्पेशलिस्ट्स को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके ऊपर आपको टेक्नोक्रैट्स को प्राथमिकता देनी चाहिए। यदि हिन्दुस्तान को औद्योगिक तरक्की की तरफ ले जाना है, यदि हिन्दुस्तान को आप को कृषि के अधिक उत्पादन की ओर ले जाना है यदि हिन्दुस्तान में आपको टेक्निकल रेवोल्यूशन लाना है तो इन क्रान्ति करने वाले लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में आपको प्राथमिकता देनी होगी। यदि सेठिया साहब को एटामिक इनर्जी कमीशन का प्रधान प्रधान मंत्री ने बनाया है तो ऐसा ही हर क्षेत्र में होना चाहिए। जितने हमारे इंजीनियरिंग और टेक्नोलाजी के डिपार्टमेंट है उनके

सेक्रेटरी नियुक्त करने का अधिकार प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्रियों को है और इसलिये इस देश को चलाने वाले नेताओं का कर्तव्य है कि वे अपनी ब्योरोक्रेसी के तंत्र को बदलें । इन भाषणों से कौन सा लाभ होने वाला है । हमारे देश में यदि आर्थिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना है, यदि हमारे देश में पोलिटिकल सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना है तो जनता के प्रतिनिधियों को अपने देश के आई० ए० एस० अफसरों के ऊपर टेक्नोक्रैट्स को प्राथमिकता देनी होगी । मेम्बर पार्लियामेंट की क्या जिम्मेदारी है । उन्हें कौन सा काम करना है ? यदि हम को देश को आर्थिक दृष्टि से और औद्योगिक दृष्टि से मजबूत बनाना है तो यह जो सात, आठ सौ पार्लियामेंट के मेम्बर हैं और यह जो हजारों विधान सभा के सदस्य हैं उनको भी अपने देश की विभिन्न योजनाओं में इंवाल्व करना होगा और नौकरशाही को भी उसमें इंवाल्व करना चाहिए । लेकिन नौकरशाही इस ढंग की है इसके लिये जिम्मेदार कौन है । इसलिये सरकार की तरफ से या जनता पार्टी की तरफ से यह कहा जाना कि आई० ए० एस० अफसर खराब है जब कि उनको अपनी तरफ से कोई बात कहने का यहां कोई मौका नहीं है, सही बात नहीं है । वे खराब नहीं है, आप खराब है । उन लोगों पर बिला वजह हमला करना ठीक नहीं है । यह सिस्टम गलत है । यह पद्धति गलत है । जब तक इसमें हम आमूलचूल परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक देश में नौकरशाही कभी भी सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का वाहन नहीं बन सकती । इसलिये इस परिवर्तन को प्राप्त करने के लिये लोकशाही और समाजवाद के सिद्धान्त को चरितार्थ करने के लिये सबसे बड़ा आवश्यक कार्य है कि सब से पहले शिक्षा में आमूल परिवर्तन किया जाय । जनता सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि देश की साठ करोड़ जनता के बेटे जो पढ़ते है उनके लिये एक प्रकार के स्कूल हों, एक प्रकार की किताबें हों, एक प्रकार के अध्यापक हों । जब एक प्रकार के स्कूलों में लड़के पढ़ेंगे तो वह एक प्रकार के हो कर निकलेंगे । जब 50 करोड़ जनता के बेटों के लिये अलग प्रकार के स्कूल होंगे, उनकी किताबें अलग होंगी, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था अलग होगी, उनके अध्यापक अलग प्रकार के होंगे, म्युनिसिपैलिटी की पब्लिक के लिये एक अलग पद्धति होगी और अलग प्रकार के अध्यापक होंगे और दिल्ली में सेंट्रल स्कूल के लिये अलग प्रकार की व्यवस्था होगी और बड़े बड़े मिनिस्टरों और नौकरशाहों के बेटों के लिये देहरादून और ऊटी के कालेज होंगे तो इस काम को कौन कर रहा है ? क्या इस काम को देश के आई० ए० एस० अफसर कर रहे हैं ? कलम की एक नोक से हिन्दुस्तान में आर्डिनेंस के माध्यम से शिक्षा में आमूल परिवर्तन किया जा सकता है । लेकिन Your party and your government lack the political will. आप में इच्छा शक्ति नहीं है, पोलिटिकल विल नहीं है । किसी योजना को लागू करने के लिये आप कोई पोलिटिकल विल नहीं रखते हैं । इसलिये You do not have the political will to implement any programme or any policy in the country.

आज हिन्दुस्तान के अन्दर जनता सरकार को काम करने की क्या जरूरत है । वह काम क्यों करेंगे । उनको जनता से क्या मतलब ? उनको तो मतलब है कि पिछली सरकार की किस तरह से रात दिन निन्दा की जाय । उनको काम से क्या मतलब ? जिस सरकार का दृष्टिकोण देश की जनता के लिये काम करने का नहीं है बल्कि पिछली सरकार की दिन रात निन्दा करना ही है वह सरकार क्या चलने वाली है । आल इंडिया रेडियो है । मैं पिछले तीन दिनों से राज्य सभा की प्रोसीडिंग्स में भाग ले रहा हूं पर मेरा नाम नहीं आ सकता । क्यों आयेगा ? यह है इनका लोकतंत्र, यह है प्रजातंत्र । लगता है आडवाणी साहब के घर के लोगों का हिन्दुस्तान का यह सूचना मंत्रालय इनका निजी है, इनकी व्यक्तिगत

[श्री कल्पनाथ राय]

सम्पत्ति है, इसलिए नहीं करता । इसलिए जब तक देश की शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन नहीं होता है, तब तक इस देश में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता ।

(*Time bell rings*)

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हम दो बातें कहना चाहते हैं । एक तो सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए । जैसे जिला परिषदें है, उनमें सबसे बड़ी पोस्ट कलेक्टर की है । मेरा कहना है कि कलेक्टर से ऊपर पोस्ट उस जिला परिषद् का जो चेयरमैन है उसकी होनी चाहिए । जिला परिषद के चेयरमैन को कलेक्टर का करेक्टर सर्टिफिकेट लिखने का अधिकार हो । हमारे पीपुल्स रिप्रजन्टेटिव को, मैम्बर पार्लियामेंट को अधिकार होना चाहिए । हम ने पब्लिक सैक्टर इकानामी को स्वीकार किया है । हमने स्टील प्लांट्स लगाये हैं, हैवी इलेक्ट्रिकल लगाये हैं, सरकारी क्षेत्र में आर्डनेंस फैक्टरीज लगाई हैं, एक मैम्बर पार्लियामेंट नहीं बल्कि 15–15 मैम्बर पार्लियामेंट को एक एक पब्लिक अंडरटेकिंग के साथ इंवाल्व कर देना चाहिए कि भाई वहां का मैनेजमेंट ठीक से काम कर रहा है कि नही, वहां उत्पादन ठीक से हो रहा है कि नही, हमारी नीतियों और प्राथमिकताओं के अनुकूल उत्पादन हो रहा है कि नही, यह देखें । तो यह सरकार की नीति. सरकार का पोलिटिकल विल है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब तक पोलिटिकल विल नही होगी तब तक देश में परिवर्तन नही हो सकता है ।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हमें उसके बाद एक और बात कहनी है । दुनिया के प्रजातांत्रिक देशों में, दुनिया के मुल्कों में जब सत्ता का परिवर्तन होता है तो सत्ता के परिवर्तन के साथ साथ उस मुल्क की ऐक्जीक्यूटिव में, कार्यपालिका में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है । जैसे अगर समाजवादी सरकार है तो उसके अनुकूल समाजवाद में विश्वास करने वाले व्यक्तियों को सेक्रेटरी के पद पर अपाइंट करता है । अगर सरकार पूंजीवादी सरकार है तो प्राइवेट सैक्टर को बढ़ावा देने वाले सैक्रटरीज को मुख्य मुख्य कार्यपालिका के स्थान पर रखती है । लेकिन मेरे मुल्क में सत्ता का परिवर्तन पहली बार हुआ है, इसलिए इस मुल्क में सत्ता के परिवर्तन के साथ साथ जो मुल्क के अन्दर टाप ऐक्जीक्यूटिव हैं उनके अन्दर भी परिवर्तन होना चाहिए ।

(*Time bell rings*)

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हमने अपने संविधान में लोकतंत्र की स्थापना की घोषणा की है, हमने अपने संविधान में भारत को सैक्यूलर स्टेट बनाने की घोषणा की है । हमने अपने संविधान में समाजवादी समाज की रचना की घोषणा की है । लेकिन समाजवाद की दिशा में जब हमने कदम उठाया तो इस मुल्क की न्यायपालिका ने, इस देश की कार्यपालिका ने उसके रास्ते में रोड़े डाले । हमारे देश की महान् नेता इंदिरा गांधी जी ने जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण का देश की जनता ने स्वागत किया, लेकिन हिन्दुस्तान की न्याय-पालिका ने बैंक राष्ट्रीयकरण के खिलाफ फैसला किया और जो देश की जनता चाहती थी, उसके खिलाफ देश की न्यायपालिका ने फैसला किया और फैसला करने में आज का जस्टिस शाह जो खुद एक बैंक में शेयर लिये था वह भी उसमें शामिल था । हमने राजा-महाराजाओं के प्रिवीपर्स को समाप्त किया, देश की करोड़ों जनता ने उसका स्वागत किया कि राजे-महाराजे इस देश से चले जाये, लेकिन इस देश की न्यायपालिका ने प्रिवीपर्स की समाप्ति के खिलाफ फैसला किया । इस मुल्क में जब जब समाजवाद की तरफ कदम उठाये गये तब तक इस मुल्क के निहित स्वार्थों ने, इस मुल्क की न्यायपालिका ने, इस मुल्क की नौकरशाही ने उस समाजवादी कदम के खिलाफ हमेशा निर्णय किया ।

THE VICE CHAIRMAN (SHRI U. K LAKSHMANA GOWDA). Please wind up.

श्री कल्पनाथ राय : जहां तक नीतियों के निर्माण का प्रश्न है, सरकार तय करती है कि किसी मुल्क की दाम नीति, शिक्षा नीति, भाषा नीति, विदेश नीति क्या होगी और उन नीतियों के कार्यान्वियन का सारा दायित्व ऐक्जीक्यूटिव या आइ०ए०एस० के ऊपर होता है। इसलिए मेरा कहना है कि चूंकि हिन्दुस्तान अब इंडस्ट्रियल और टेक्नोलाजिकल रेवलूशन के दौर से गुजर रहा है, इसलिए जर्नलिस्ट्स की अपेक्षा स्पेशलिस्ट्स और आइ०ए०एस० की अपेक्षा टेक्नोक्रैट्स को ऐडमिनिस्ट्रेशन में प्राथमिकता देकर हमें अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहिए। धन्यवाद।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह यादव) : उपसभाध्यक्ष जी, डा० रजत कुमार चक्रवर्ती ने संविधान के अनुच्छेद 312 में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव रखा। संविधान के संशोधन के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव उन्होंने रखा है, उसको अगर गौर से देखा जाए तो अर्थ यही निकलता है कि आल इंडिया सर्विसेज की एक नई व्यवस्था कायम की जाए। और जिसका नाम अखिल भारतीय सेवा या जिसे अखिल भारतीय प्रशासन और प्रबन्ध सेवा नाम दिया जाय। साथ ही साथ डा० चक्रवर्ती को यह आभास हुआ कि आई० ए० एस० अधिकारियों के मुकाबले वैज्ञानिकों और तकनीकी लोगों को वह स्थान नहीं मिलता है जो उनको मिलना चाहिए। इसलिए लेटर एन्ट्री के आधार पर एक नई अखिल भारतीय सेवा का प्रपोजल उन्होंने रखा है। मैं आरम्भ में यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस प्रस्तावित विधेयक के उद्देश्य की पूर्ति अनुच्छेद 312 का जो संशोधन करने के लिए प्रस्ताव रखा गया है, उस संशोधन के बिना ही इसकी पूर्ति हो जाती है। संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्य सभा अपने उपस्थित सदस्यों के 2/3 मतों के द्वारा कोई भी संकल्प पास करा सकती है और उसमें परिवर्तन कर सकती है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस प्रकार के एमेन्डमेंट को लाने की आवश्यकता नहीं है और न ही कोई धारा जोड़ने की आवश्यकता है।

जहां तक डा० चक्रवर्ती जी की इन बातों की तरफ मेरा ध्यान जाता है कि हमारे वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकों को उचित स्थान पर प्रतिष्ठित किया जाय, उनकी इन भावनाओं से हम सहमत हैं। इस संबंध में आप अगर आंकड़े देखें तो यह पाएंगे कि हमारी अखिल भारतीय सर्विसेज में इस समय भी ऐसे अधिकारी मौजूद हैं जो नान-आई० ए० एस० और नान-आई० पी० एस० हैं। उनके कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर आप इनको ध्यान से देखें तो आप यह स्थिति पाएंगे कि ऐसे अधिकांश और अनेक पदों पर जहां तकनीकी व्यक्तियों और विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है वहां पर गैर आई० ए० एस० वालों को ही नियुक्त किया जा रहा है। उदाहरण के लिए आज भारत सरकार के 63 सचिवों में से 29 पर गैर-आई० ए० एस० व्यक्तियों को रखा गया है। इसी प्रकार से अवर सचिव या अन्डर सेक्रेटरी तथा उसके ऊपर के स्तर के भारत सरकार के अधीन जो 2015 पद है उनमें 28.6 प्रतिशत पदों पर आई० ए० एस० अधिकारी नियुक्त है। इनके अलावा बाकी सारे अधिकारी गैर आई० ए० एस० हैं। गैर आई० ए० एस० सचिवों के संबंध में मैं आपको कुछ कंक्रीट एक्जाम्पल देना चाहता हूं। इस समय डा० मनमोहन सिंह वित्तीय कार्य और बैंकिंग विभाग के सचिव हैं। ये आई० ए० एस० नहीं है। श्री मनतोश सोंधी जो इस्पात और खान मंत्रालय के सचिव है और श्री वी० कृष्णमूर्ति भारी उद्योग विभाग में सचिव है, ये भी नान आई० ए० एस० है। इसी प्रकार से श्री एस० एस० मराठे उद्योग विभाग में सचिव है और श्री एम० एस० स्वामिनाथन आई० सी० ए० आर० में सचिव व

[श्री कल्पनाथ राय]

डायरेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त हैं। ये सब लोग नान आई० ए० एस० हैं। ऐसा लगता है कि पिछली बार जब यह बिल पेश किया गया था तो उस समय यह स्थिति थी कि आई० ए० एस० वालों की तरफ ही ज्यादा ध्यान दिया जा रहा हो। लेकिन अब मैं यह बताना चाहता हूं कि अब वह स्थिति नहीं है और ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति के संबन्ध में जो मेथड अपनाया जाता है वह इस प्रकार से है—

Recruitment to the Indian Administrative Service is made by the following methods:

(1) Direct recruitment through an annual competitive examination held by the Union Public Service Commission. The direct recruitment is against 66-2/3 per cent of the total number of vacancies available in the various State Cadres of the Service.

(2) By promotion of substantive members of the State Civil Service. Till 5th July, 1977 the number of posts which could be filled by promotion was limited to 25 per cent of the senior duty posts in State Cadre of the Service. This percentage has now been increased to 33.1/3 per cent.

(3) By selection, in special cases from among persons who held in a substantive capacity gazetted posts in connection with the affairs of a State and who are not members of the State Civil Service. This provision enables the Commission to recruit to the Service any person of outstanding ability and merit serving in connection with the affairs of the State who is not a member of the State Civil Service. Not more than 15 per cent of the posts in the promotion ceiling in each State Cadre can be filled through this method. This percentage has now been increased to 33.33.

नियुक्तियों के इन तरीकों को देखते हुए प्रस्ताविन विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है।

तो मैं यह बताना चाहता हूं कि स्टेट सर्विसेज, जो सिविल सर्विसेज है, वहां से जो अधिकारी आई० ए० एस० विंग में आते हैं, उनका औसत 33 प्रतिशत रखा गया है, जबकि यह पहले 25 प्रतिशत था। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको यह बताना चाहता हूं और यह बताने के लिये सहर्ष तैयार हूं कि जो भावनायें डा० चक्रवर्ती जी ने दिखाई हैं कि हमारे वैज्ञानिकों के साथ, तकनीशियनों के साथ जो व्यवहार होता है, उसके साथ इनफिरियरटी की भावना से काम लिया जाता है या समझा जाता है, यह बात नहीं है। अगर कोई इस बात को अपने से समझता हो, तो सरकार और मैं उसके लिये जिम्मेदार नहीं हैं। हम वैज्ञानिकों का आदर करते हैं, हम तकनीशियनों का आदर करते हैं, हमारी सरकार उनका सम्मान करती है। उनका....

SHRI KALP NATH RAI: I want to ask one question. Are you going to appoint, as a matter of your policy engineers and doctors as Deputy Secretaries, Additional Secretaries and Secretaries?

SHRI NARSINGH YADAV: मैं बात कह रहा हूं। आप इन्टरेस्ट न करें।

SHRI KALP NATH RAI: I put a question.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): In his reply, he is clarifying that.

SHRI KALP NATH RAI: I put a question. Is your Government going to adopt a policy to appoint doctors, engineers and technologists as Secretaries and Additional Secretaries?

SHRI NARSINGH YADAV: As a policy, the Government will decide it.

कैबिनेट डिसीजन लेगी । जिनकी नियुक्ति कर दी गई है, उनके अलावा बाकी के लिये कैबिनेट डिसीजन लेगी और जो माननीय सदस्य सुझाव दे रहे हैं, उन सुझावों को ध्यान में रखते हुए इस बात को बताया जायेगा । तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को इस प्रकार की भावना से अभिग्रसित होने की आवश्यकता नही है और जो आपके वेल्युएबल सुझाव हैं, उन सुझावों को ध्यान में रखते हुए इस बात की ओर जरूर ध्यान दिया जाएगा कि ऊंचे पदों मे नियुक्ति के लिये जो कि वर्तमान पद्धति चल रही है उसको क्रियाशील बनाया जाय, उनको ऐक्टिव किया जाय ।

दूसरी चीज जो है और जो स्थिति मैंने आपके सामने बताई, उसके सबन्ध में मैं एक बात और कहना चाहता हूं । वह यह कि 1974 में तत्कालीन वित्त मंत्री ने भी वेतन आयोग की रिपोर्ट पर संसद के सामने अपने वक्तव्य में सरकार की बुनियादी नीति को दोहराते हुए बताया था कि हमारे तकनोशियनों और हमारे साइंटिस्टों को ऊंचा स्थान मिलना चाहिए । हमारी सरकार किसी भी हालत में इस प्रकार के लोगों के प्रति कोई अन्याय करने को तैयार नही है, उनके साथ जस्टिस जरूर होगा और सरकार इस तरह के काम क आगे बढ़ायेगी ।

कुछ साथियों ने अपने सुझाव या अपनी कुछ बातें सदन के सामने रखी हैं और कुछ लोगों ने कहा कि पिछली सरकार ने यह किया, अगली सरकार क्या करेगी ? मैं इसकी बहस मे नहीं जाना चाहता । हम समझते हैं और पिछली सरकार के लोग भी यह समझते हैं कि कुछ ऐसी बातें है जिन्हें सोचना जरूरी है । दोनों पक्षों के लोगों ने आई० ए० एस० के पक्ष में और विपक्ष में अपने विचार प्रक किये हैं । उनके अपने अपने अनुभव है, उनकी अपनी-अपनी बातें है । कोई क्रियेटिव सुझाव आप देंगे तो उस पर सरकार जरूर विचार करेगी । म लोग न तो किसी आई० ए० एस० को हीनता की भावना से देखना चाहते हैं और न किसी अन्य भावना से या दृष्टि मे देखना चाहते हैं ।

एक बात जो श्री कल्पनाथ राय ने कही है कि शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन होना चाहिए, उससे मैं सहमत हूं । यह एक बुनियादी सवाल है और यह पद्धति बहुत पुराने जमाने से चली आ रही है । सरकार के सामने क्या परिस्थितियां है, क्या बातें हैं कि जो यह नहीं हो रहा है, इस बारे में पहले से भी सरकार से मांग की जा रही थी, यह सब शिक्षा विभाग का काम है और शिक्षा मंत्रालय इसको देखेगा ।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही ने सवाल किया था कि आई० ए० एस० पर कोई नियंत्रण नहीं रहा है । मैं बताना चाहता हूं कि इस वर्तमान सरकार के अधीन जितने भी आई० ए० एस० अधिकारी हैं, वे अनुशासित रहेंगे और जो अनुशासन के अन्दर नहीं रहेगा और आप उसके बारे में सबूत देंगे तो निश्चित रूप से उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी और इसके लिए सरकार पीछे नहीं रहेगी । सरकार उस काम में आगे रहेगी । तो हम इन शब्दों के साथ, और बातों को अपने साथ रखते हुए माननीय सदस्य से निवेदन करेंगे कि अपना विधेयक वापिस ले लें ।

श्री कल्प नाथ राय : आदरणीय उप सभाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पूछना चाहता हूं क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि Is he going to give preference to technocrats as compared to the I.A.S officers?

श्री नरसिंह यादव : यह पालिसी मैटर है । गवर्नमेंट इस पर विचार करेगी । मैंने आपको पहले बता दिया है कि इसके बारे में कैबिनेट डिसाइड करेगी । जैसा कि डा० चक्रवर्ती ने बताया कि इसमें कम्पलीकेशंस बढ़ेंगी । सब बातों को देखा जाएगा । अगर

[श्री नरसिंह यादव]

आप कंक्रीट सुझाव भेजेंगे तो उन पर विचार किया जाएगा ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Dr. Chakrabarti, do you want to reply now or next time? There are only three or four minutes and the House has to be adjourned at 5 o'clock.

DR. RAJAT KUMAR CHAKRABARTI: Sir, I will reply now. I will take only another five minutes.

SHRI BIPINPAL DAS (Assam): Why don't you reply next time?

DR. RAJAT KUMAR CHAKRABARTI: All right I will reply next time.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): The House stands adjourned till 11 A.M. on Monday, the 5th December, 1977.

The House then adjouned at fifty-seven minutes past four of the clock till eleven of the clock on Monday, the 5th December, 1977.

GMGIPMR—Job I—1318 R.S.—JC 4222—30-1-78—400